(v) ALLEGED CLOSING DOWN OF FLOOR MILLS IN BIHAR DUE TO REDUCED SUPPLY OF WHEAT QUOTA.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कौडरमा): देश के सभी राज्यों में बड़ी चक्कियां तथा रोलर फ्लोर मिल्स के द्वारा जन वितरण हेतु गेहूं पीसने के लिए केन्द्र सरकार मासिक गेहूं आबंटित करती रही है । अप्रैल 1982 में भारत सरकार ने बिहार की 22 बड़ी चक्कियों को 2610 मी. टन तथा 20 रोलर फ्लोर मिलों को 16390 मी. टन गेहूं आबंटित किया । मई 1982 से केन्द्र सरकार ने बड़ी चक्कियों के कोटे काट कर केवल बड़ी मिलों के लिए गेहूं आबंटित किया । इससे 28 बड़ी चक्कियां बंद हो गई हैं । ये सभी बड़ी चक्कियां लघु-उद्योग के अन्तर्गत निबंधित हैं और इन चक्कियों में कार्यरत सैंकड़ों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है । बिहार की जनता फ्लोर मिलों का आटा व्यवहार में कम से कम पसन्द करती है क्योंकि उससे अच्छा बड़ी चक्कियों का आटा स्वास्थ्यवर्धक समझती है । छोटा नागपुर का क्षेत्र इस वर्ष अकाल से पीड़ित है । इन चक्कियों से सैंकड़ों मजदूरों को रोजी रोटी मिलती थी । वह बंद हो गई हैं । बिजली की मिनिमम गारंटी एवं बैंक ऋण जमा तथा अनावश्यक सूदखोरी इन छोटे उद्योगों पर वज्राघात के समान है ।

अस्तु, श्रीमन् कृषि एवं आपूर्ति मंत्री से आग्रह है कि अन्य राज्यों की तरह तुरन्त बिहार की बड़ी चक्कियों को 3226 मी. टन मासिक गेहूं का कोटा चालू किया जाए और सौतेला व्यवहार बिहार के इन लघु उद्यमियों के साथ नहीं किया जाए ।

(VI) ALLEGED REDUCTION IN QUOTA OF RICE AND WHEAT TO BIHAR.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): वर्षा नहीं होने के कारण सम्पूर्ण बिहार तपती धूप और भीषण गर्मी में जल रहा है । आदरा नक्षत्र की वर्षा में किसान धान का बीज खेतों में डालते थे । परन्तु उसके फेल हो जाने से किसानों में सर्वत्र कुहराम है । जिन इलाकों में नहरें हैं, उन में भी पानी नहीं रहने से स्थिति और भी खराब हो गई है । उधर नहर विभाग के अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं । नलकूपों की स्थिति भी अच्छी नहीं है । जो कुछ नलकूप ठीक हैं भी उन से काम नहीं चल पा रहा है ।

ऐसी स्थिति में थोक और खुदरा दोनों मूल्यों में वृद्धि हो रही है । गल्ला चोर और मुनाफाखोर जनता को लूटने की ताक में लगे हुए हैं । बिहार में खाद्यान्न की स्थिति गम्भीर बनती जा रही है ।

बिहार में राशन की दुकानों में गल्ला सप्लाई करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक माह पचास हजार टन चावल और चौबीस हजार टन गेहूं देती थी जो वहां की आवश्यकता को देखते हुए कम था । परन्तु आश्चर्य और दुःख की बात है कि भारत सरकार ने उस में भी कटौती कर दी है । चावल का कोटा पचास हजार टन से बीस हजार टन और गेहूं का कोटा चौबीस हजार हजार टन से बीस हजार टन प्रतिमाह कर दिया है । इसका साफ मतलब है कि सरकार आम उपभोक्ताओं को संकट की इस घड़ी में मुनाफाखोरों और गल्लाचोरों के रहमो-करम पर छोड़ देना चाहती है । इसका परिणाम स्पष्ट है। न मालूम कितने लोग भूखों मर जाएंगे क्योंकि उन्हें राशन की दुकानों से खाद्यान्न मिलेगा नहीं और क्रय-शक्ति में ह्रास होने के कारण बाजारों से वह आवश्यक सामग्री खरीद नहीं सकेंगे ।

बिहार सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने भारत सरकार की खाद्यान्न कटौती की इस नीति का विरोध कर बिहार की करोड़ों जनता की आवाज को बुलन्द किया है ।

मेरा भारत सरकार के कृषि मंत्री से अनुरोध होगा कि वह बिहार को मिलने वाले पचास हजार टन चावल और चौबीस हजार टन गेहूं के कोटे में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करें । मेरा यह भी अनुरोध होगा कि वह बिहार की वर्तमान गम्भीर स्थिति को देखते हुए उसके कोटे में और वृद्धि करें ताकि कोई भूख से नहीं मरने पाए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Madhu Dandavate. Professor, after you read it, the Minister has agreed to reply.